

भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय : 'गरीब कल्याण'

'गरीब कल्याण' देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-राजग नीत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की नीतियों और शासन मॉडल का मार्गदर्शक दर्शन है। भाजपा सरकार की जन-समर्थक नीतियां हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा में निहित हैं। भारतीय राष्ट्रवाद सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय या भाषाई पृष्ठभूमि के बावजूद साझा भविष्य में समावेशिता और विश्वास की नींव पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शासन दर्शन भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करता है: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। भाजपा सरकारों ने इस आदर्श वाक्य को प्रदेश में और जहां भी वे गठबंधन सरकारों में हैं, अपनाया है।

महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1.70 लाख करोड़ रुपये की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण' (पीएमजीकेवाई) योजना और 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान (पीएमजीकेवाई सहित) की शुरुआत की। यह 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों और एमएसएमई को आय समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 31.9 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण का प्रावधान आदि सुनिश्चित किया गया है। सरकार, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को महामारी के बाद की दुनिया और त्वरित आर्थिक पुनरुत्थान के लिए तैयार करने के लिए स्पर्श कर रही है। नतीजतन, महामारी और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण हुए व्यवधान के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट जारी है।

जैसे-जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश करेगा, हमारी प्रगति की गति और तेज होगी। भाजपा के सुशासन मॉडल का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार रहा है। मुफ्तखोरी की राजनीति, जिसका राजकोषीय स्थिरता पर गंभीर परिणाम होता है, के विपरीत, भाजपा सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य क्षमता निर्माण में सहायता करके सत्ता को सशक्त बनाना है। ऐसी नीतियों के पीछे प्रेरक शक्ति गरीबों को सशक्त बनाना और व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता निर्माण करना है।

वे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हैं और पर्याप्त प्रावधान द्वारा समर्थित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं गरीबों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करती हैं; 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' घरों को बिजली प्रदान करती है; प्रधानमंत्री उज्वला योजना एलपीजी सिलेंडर प्रदान करती है; घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल योजना या स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य वंचित वर्गों को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करना है।

इसी समय, 16 प्रदेशों में डबल-इंजन वाली राजग सरकारों ने इसी तरह त्वरित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। गरीबों के उत्थान और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने के लिए डबल-इंजन वाली राजग सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर पहल की गई हैं।

अरुणाचल प्रदेश

ग्राम स्तर पर सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 'सेवा आपके द्वार 2.0' लॉन्च किया गया है- 12 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए 1000+ शिविर आयोजित किए गए हैं। 'आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश' 7,387 से अधिक किसानों और 719 एसएचजी के लाभार्थियों के साथ "आत्मनिर्भरता" को बढ़ावा देने वाली एक फ्रंट एंडेड सब्सिडी फ्लैगशिप योजना है। मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना स्थानीय नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक की गुणवत्ता और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना शुरू की गई है।



भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय: 'गरीब कल्याण'

असम

असम सरकार ने प्रदेश में गरीब परिवारों को प्रति माह 1250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'ओरुनोदोई' योजना शुरू की है, जिससे 19 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए असम आरोग्य निधि (एएएन) बीपीएल परिवारों और 10,000/- रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को सामान्य और विशेष उपचार के लिए 1,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा, स्वामी विवेकानंद असम युवा अधिकारिता (SVAYEM) योजना असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। स्वनिर्भर नारी - आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर असोम योजना भी शुरू की गई है और पहले चरण में लगभग 4 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला है।

गोवा

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, चार या अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए 4 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। गृह आधार योजना के जरिए 1500 रुपये की मासिक सहायता जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से गृहणियों को वितरित की जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को एक लाख रुपये की सहायता उनकी बेटी की शादी में मदद हेतु दी जाती है। इसके अलावा, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांगों और एचआईवी / एड्स रोगियों को 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन हस्तांतरित की जाती है।

गुजरात

मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो दो लाख रुपये या पाठ्यक्रम शुल्क का 50% छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए है, जिन्होंने 12वीं कक्षा के विज्ञान विषय में 80 या अधिक पर्सेंटाइल प्राप्त किया हो या जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो। गुजरात गंगा स्वरूप योजना एक विधवा पेंशन योजना है जिसके तहत 1250 रुपये प्रति माह की पेंशन देती है। इस योजना के माध्यम से पूरे गुजरात के 33 जिलों में 3.70 लाख महिलाओं को पेंशन प्रदान की गई है। मां वत्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम योजना का एक विस्तार, इसमें अब निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनको पहले बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, ऐसे परिवारों को प्रति परिवार 3 लाख रुपये का कवरेज प्रदान किया जा रहा है। घरों की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना और उपयोग को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा के बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर रूफटॉप योजना शुरू की गई है। इसकी स्थापना के बाद से राज्य में 3,91,830 आवासीय रूफटॉप सौर पैनल सिस्टम स्थापित किए गए हैं।

हरियाणा

हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। म्हाारा गांव जगमग गांव के तहत 5487 गांवों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। "महिला एवं किशोरी सम्मान" के तहत बीपीएल परिवारों की 22.5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत कमजोर आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जाति/विमुक्त और टपरीवास को 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। गरीब कल्याण के सिद्धांत पर- सबसे गरीब का आर्थिक उत्थान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए 1 लाख परिवारों को शिक्षा, कौशल विकास जैसे उपायों का एक अनुरूप पैकेज दे रही है और उनकी आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।





भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय : 'गरीब कल्याण'

कनटिक

अंतिम-मील वितरण के उद्देश्य से जनसेवक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 58 सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और अब तक 95000+ आवेदनों का निपटान किया जा चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दो हजार रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए रायता विद्या निधि छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसमें अब तक 464.15 करोड़ रुपये की लागत से 10.19 लाख छात्रों को कवर किया जा चुका है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री समर्थ योजना शुरू की गई है, जो 5 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान कर रही है। युवाओं के उत्थान के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में बाबू जगजीवन राम स्व-रोजगार योजना शुरू की गई है, जिससे 22,400 युवा लाभार्थियों को स्वरोजगार का लाभ मिलता है। इसी तर्ज पर स्वामी विवेकानंद युवशक्ति कार्यक्रम के तहत 28 हजार गांवों में, प्रत्येक समूह के लिए 1.5 लाख रुपये के बीज धन के साथ युवाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है। इसके अलावा, कयाक्स योजना के माध्यम से गांवों में 3.3 लाख पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई आदि का समर्थन किया जा रहा है।

मणिपुर

राज्य सरकार ने किसानों को वैध और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने और जलवायु जोखिमों के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए एक मोबाइल-आधारित कृषि-सलाहकार सेवा 'लौमिसिंगी पाओजेल्' शुरू की है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों, निराश्रित और विधवाओं को प्रति माह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शोथाराबासिंगी तेंगबांग योजना 2 लाख रुपये के बीमा और मुफ्त परिवहन सेवाओं के साथ-साथ दिव्यांगों को देखभाल हेतु भत्ता प्रदान करती है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पीएम-जेएवाई, पीएम आवास योजना, एसपीएम रूबन मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश

निराश्रितों को पोषण प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने दीन दयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 100 केंद्र स्थापित किए गए हैं, यहां गरीबों को अत्यधिक रियायती दर पर भोजन परोसा जाता है। योजना के तहत 70 लाख से अधिक भोजन परोसे जा चुके हैं। सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति युवाओं को वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 'भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना', 'टंच्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' और 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्तपोषण योजना' जैसी कई योजनाएं शुरू कीं। वहीं, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना ने प्रदेश भर में 2.5 लाख से अधिक युवाओं को मुफ्त कौशल विकास प्रदान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वंचितों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व उपचार मिले, इसके लिए एमपी राज्य बीमारी सहायता निधि शुरू की गई है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को 2 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है।



भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय : 'गरीब कल्याण'

महाराष्ट्र

सभी को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए दीवाली के समय, एक योजना 'आनंदचा सिद्धा' शुरू की गई थी, जिसमें आवश्यक सामग्री (रवा, चीनी, तेल) से युक्त खाद्य किट मात्र 100 रुपये की रियायती दर पर वितरित की गई थी। समाज के सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएचडी करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दो साल के लिए 35 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गरीब कल्याण के इसी दर्शन पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को 18 हजार रुपये दिए जाते हैं। महाराष्ट्र प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार 16 लाख किसानों को 4700 करोड़ रुपये दिए गए हैं, यह ऐसे किसान हैं, जो समय पर अपना अल्पकालिक फसली ऋण चुका रहे हैं। बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए मांझी कन्या भाग्यश्री योजना शुरू की गई, जो 7.5 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों में बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं अस्मिता योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.6 करोड़ सेनेटरी पैड अत्यधिक रियायती मूल्य पर बेचे गए हैं। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य से जलयुक्त शिवर अभियान नामक एक बहुत लोकप्रिय जल संरक्षण योजना शुरू की गई थी जो ग्रामीणों और किसानों को उनके भरण-पोषण के लिए अत्यधिक मदद करेगी।

नागालैंड

सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना पूरी आबादी को कवर करने के लिए शुरू की गई थी, जिससे नागालैंड को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से लैस किया जा सके। प्रदेश जल जीवन मिशन युद्धस्तर पर चला रहा है और 2023 तक अपने सभी 3.8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करेगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीएम माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया था। यह अपने पहले वर्ष में 1500+ उद्यमियों के लिए अवसर पैदा कर रहा है। पीएम ग्राम सड़क योजना सीमावर्ती गांवों सहित प्रदेश के दूरदराज के हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार कर रही है। इसके अलावा, निवासियों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना और किफायती किराया आवासीय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पुदुचेरी

बेघर गरीबों के लिए पेरुन्थलाइवर कामराजार आवास योजना (2 लाख रुपए तक की सब्सिडी) और लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास योजना शुरू की गई है। रोजगार सृजित करने और कौशल उन्नयन के लिए कारीगरों/राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। इससे शौचालय वाले घरों की संख्या में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। झुग्गीवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार किए जा रहे हैं। शहरी परिदृश्य को बदलने, पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय योजना अमृत का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पीएम आवास योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, 822.64 करोड़ रुपये की लागत से 105 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इससे कनेक्टिविटी, परिवहन, कानून व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।





भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय : 'गरीब कल्याण'

त्रिपुरा

त्रिपुरा में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। राजग सरकार के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों की औसत आय में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चाय बागान के श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प' का शुभारंभ किया गया। पहली बार सरकार ने भूमिहीन स्थानीय नागरिकों के लिए, भूमि अधिकारों के सीमांकन के लिए बने अधिकार ऐप को लॉन्च किया। इसके माध्यम से 1.2 लाख नागरिकों को भूमि का पट्टा प्रदान करने में मदद मिली है। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 38 हजार से बढ़कर 3.45 लाख से अधिक हो गई है। इन्हें वित्तीय संस्थानों से जोड़कर गरीब परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता के नए द्वार खोल दिए गए हैं। इस योजना ने उन्हें एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत लाया है, जिससे आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित हुई। 75 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के साथ इस योजना ने चाय बागान श्रमिकों के 7000+ परिवारों को लाभान्वित किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने राजग सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 34,528 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में लगभग 75 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि गतिविधियों पर निर्भर करती है। दीन दयाल उपाध्याय किसान सहकारी कल्याण योजना छोटे और सीमांत किसानों और कृषि समूहों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा, स्व-रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। बड़े ऋणों में 15-20 प्रतिशत और नैनो श्रेणी के ऋणों में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी के साथ, इसका उद्देश्य प्रदेश के भीतर और अन्य प्रदेशों में पलायन करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं को रोकना है। भौगोलिक रूप से कठिन इलाके में सरकार ने हेली एम्बुलेंस योजना भी शुरू की है। इसमें गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सेवाओं का प्रावधान है और यह आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड से भी जुड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। दूर-दराज के हिस्सों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में राजस्व पुलिस की प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रदेश में नियमित पुलिस प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन को अधिसूचित किया।



भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

16, 17 जनवरी 2023

राष्ट्रीय कार्यसमिति का वक्तव्य

'डबल इंजन' राजग सरकारों की अटूट निष्ठा का विषय : 'गरीब कल्याण'

उत्तर प्रदेश

एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने 100 दिन में 10 हजार युवाओं को रोजगार दिया। इसके अलावा, भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 लाख से अधिक हस्तशिल्प पुरुषों, कामगारों और छोटे व्यापारियों को 16,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। गन्ना किसानों को दिसंबर, 2022 तक रिकॉर्ड 1.84 लाख करोड़ रुपये समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत काम के दौरान मृत्यु/दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही वे सभी नागरिक जिनके पास बेहिंसाब पैसा है, वे अपनी अघोषित आय को गरीब कल्याण योजना में जमा करा सकते हैं, इसका उपयोग गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत नवजात कन्या की मां को 5100 रुपये का बॉन्ड और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत सभी भूमिहीन खेत श्रमिकों को बिना किसी प्रीमियम राशि के 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है। कोविड के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भाजपा सरकार ने 23 लाख दिहाड़ी मजदूरों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए।

जैसा कि डबल इंजन वाली राजग सरकार की उपरोक्त पहलों से देखा जा सकता है, 'गरीब-कल्याण' पार्टी की आधारशिला है। आज हम जनता और सरकार के बीच संबंध में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'संरक्षण' की राजनीति से हटकर 'विकास' की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। सरकारी नीतियों को लागू करने में भारत की मुख्य चुनौतियों में यह रही है कि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति जाति और पहचान के आधार पर नीतियों को प्रभावित करते आए हैं, लेकिन भाजपा सरकारों ने इस रवैये को रोकने में सफलता हासिल की है।

आवास, बिजली या गैस सिलेंडर जैसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की अभूतपूर्व डिलीवरी, आधार और डीबीटी जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मुद्रा और जनधन योजना जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक सुरक्षा कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित किया गया है। लाभार्थियों और गरीबों को वह लाभ मिला रहा है, जिसके वे हकदार थे। सार्वजनिक वस्तुओं के इस सार्वभौमिक और प्रत्यक्ष प्रावधान और निजी वस्तुओं के सार्वजनिक प्रावधान ने जमीन पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे प्रदेश और जनता के बीच संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है।

'गरीब कल्याण' की मूल विचारधारा के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सही मायने में गरीब और कमजोर एवं अंतिम पंक्ति के नागरिकों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

